

23 April The Hindu

Line of Caution (LOC)

संदर्भ

- गृह मंत्रालय ने 19 अप्रैल को आदेश जारी कर जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) व्यापार पर रोक लगा दी। भारत सरकार ने यह कदम एलओसी के पार वाले व्यापार मार्गों का पाकिस्तान स्थित तत्वों द्वारा गैर कानूनी हथियारों, मादक पदार्थों और जाली नोट आदि भेजने के लिए दुरुपयोग किये जाने की खबरें मिलने के बाद उठाया है।
- उल्लेखनीय है कि एलओसी व्यापार जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आरपार की स्थानीय आबादी के बीच आम इस्तेमाल वाली वस्तुओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित है। दो व्यापार सुविधा केंद्रों सलामाबाद, उरी, जिला बारामूला और चक्कन-दा-बाग, जिला पूंछ के माध्यम से एलओसी व्यापार की अनुमति है। यह व्यापार सप्ताह में चार दिन होता है और यह वस्तु विनियम प्रणाली और जीरो ड्यूटी के आधार पर किया जाता है।
- पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा वापस लेने के बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ व्यापार पर रोक लगा दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एलओसी के रास्ते होने वाले व्यापार में कुछ व्यापारिक कार्यों को अंजाम देने वाले लोग आतंकवाद व अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से बहुत करीब से जुड़े हैं, इसलिए जम्मू और कश्मीर में सलामाबाद और चक्का-दा-बाम में एलओसी व्यापार को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
- इस बीच विभिन्न एजेंसियों से मिलकर सख्त नियम बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके नियंत्रण रेखा के जरिए होने वाले व्यापार मार्गों के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।
- **दोनों देशों में जीरो शुल्क पर हफ्ते में 4 दिन होता था कारोबार**
- नियंत्रण रेखा के जरिए पाक के कब्जे वाले कश्मीर के बीच व्यापार का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर बनाए गए तथा उगाए गए उत्पादों के आदान-प्रदान को सुगम बनाना था।
- यह व्यापार बारामूला जिले और उरी तथा पूंछ जिले के केंद्रों से हो रहा था। इसके लिए हफ्ते में चार दिन निर्धारित थे।
- यह व्यापार वस्तु विनियम और जीरो सीमा शुल्क पर आधारित था। इस मार्ग पर सीमा शुल्क नहीं होने के कारण यह भी आशंका थी कि इसका दुरुपयोग भविष्य में और बढ़ सकता है।
- सरकार के इस कदम की आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि, एक व्यापार समझौते के उल्लंघन का समाधान नियमों को सख्ती से लागू करना है न कि सामानों का आदान-प्रदान रोकना, नियंत्रण रेखा के दोनों ओर बहुत से लोगों की आजीविका इस व्यापार से जुड़ी हुई थी।
- एलओसी व्यापार से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता था। इस व्यापार की शुरुआत अक्टूबर 2008 में 'वस्तु विनियम व्यापार' के रूप में की गई थी। इसमें लगभग 1.6 लाख से अधिक लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था। व्यापार ज्यादातर स्थानीय वस्तुओं का और परिवहन में कार्यरत समुदाय भी स्थानीय होता था।
- इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। एलओसी व्यापार दोबारा शुरू करने से संबंधित फैसले पर उसके बाद पुनर्विचार किया जाएगा।

आतंकवाद व दक्षिण एशिया

- श्रीलंका में हाल ही में ईस्टर वाले दिन हुए हमले जिसमें तीन चर्च और तीन लग्जरी होटल में आठ बम विस्फोट से 215 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 500 लोग घायल हुए।
- इस हमले के पीछे इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक के भाषणों से प्रभावित होने वाले आतंकवादियों के शामिल होने की बातें सामने आयी हैं।
- इस क्षेत्र में यह पिछले 15 वर्षों का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। 1970 और 2017 के बीच दुनिया भर में हुए आतंकवादी हमलों और उनमें हताहतों के विश्लेषण से पता चलता है कि दक्षिण एशिया दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है।
- वैश्विक आतंकवाद पर सबसे व्यापक ग्लोबल टेरर डाटाबेस के विश्लेषण की भयावह तस्वीर बताती है कि 1970 से 2017 यानी पिछले 48 वर्षों में दुनिया भर में हुए कुल 1.8 लाख आतंकी हमलों में से 31 फीसद हमले दक्षिण एशिया में हुए जिनमें दुनिया की कुल 29 फीसद मौतें हुईं।
- कुल आतंकी वारदातों के मामले में मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) सबसे आगे रहे।

दक्षिण एशिया में बड़ी आतंकी वारदातें:

- 2002 और 2017 के बीच, दक्षिण एशिया में लगभग 32 हजार आतंकी हमले हुए, जिसमें लगभग 60 हजार लोगों की जान गई।
- 21 अप्रैल, 2019, श्रीलंका, 290 मौतें, 26 नवंबर, 2008, मुंबई, 150 मौतें, 2014, पेशावर, 150 मौतें हुईं।
- आठवें दशक की शुरुआत में दक्षिण एशिया आतंकवादी हमलों से बहुत हद तक मुक्त था। धीरे-धीरे इस क्षेत्र में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ती गई। 1970 में यहां 651 आतंकी हमले हुए।
- 2014 में यह आंकड़ा 17 हजार पार हो गया।
- 2018 की अपनी नवीनतम रैंकिंग में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने तीन दक्षिण एशियाई देशों (अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान) को आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल किया है।
- इस सूची में इराक पहले और अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर है। वही पाकिस्तान पांचवें और भारत सातवें स्थान पर है।